भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4987

01 अप्रैल, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: राष्ट्रीय बागवानी मिशन

4987: **श्री नरेश गणपत म्हस्के:**

श्रीमती शांभवी:

श्री रवीन्द्र दत्तराम वायकर:

श्री राजेश वर्मा:

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मार्च, 2025 तक राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत लाए गए कुल क्षेत्रफल का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विगत पांच वर्षों के दौरान मिशन के अंतर्गत बागवानी की नई किस्में शुरू की गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री और सूक्ष्म सिंचाई द्वारा फसलों की उत्पादकता पर इस योजना का क्या प्रभाव पड़ा है;

(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान मिशन के माध्यम से सृजित रोजगार संबंधी आंकड़ों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विगत पांच वर्षों के दौरान मिशन के अंतर्गत सृजित फसलोपरान्त प्रबंधन और विपणन अवसंरचना की संख्या के संबंध में विस्तृत आंकड़े क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) एवं (ख): राष्ट्रीय बागवानी मिशन, समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) की एक उप-योजना है, जिसे देश में बागवानी के समग्र विकास के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014 से कार्यान्वित किया जा रहा है। एमआईडीएच योजना की शुरुआत से अर्थात वर्ष 2014-15 से 2024-25 तक, बागवानी फसलों के तहत 13.97 लाख हेक्टेयर का अतिरिक्त क्षेत्र कवर किया गया है। सभी बागवानी फसलें, चाहे उनकी किस्में कुछ भी हों, एमआईडीएच योजना के तहत कवर की जाती हैं।

(ग): गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री और सूक्ष्म सिंचाई सहित एमआईडीएच योजना के विभिन्न घटकों ने बागवानी फसलों की उत्पादकता पर सकारात्मक प्रभाव दिखाया है जो 2019-20 में 12.10 मीट्रिक टन/हेक्टेयर से बढ़कर 2024-25 में 12.56 मीट्रिक टन/हेक्टेयर हो गई है (प्रथम अग्रिम अनुमान)।

(घ) एवं (ङ): पिछले पांच वर्षों के दौरान, शीतागार/सी.ए. भंडारण, पैक हाउस, राइपनिंग चैंबर, रीफर वाहन, प्राथमिक/मोबाइल/न्यूनतम प्रसंस्करण इकाई, संरक्षण इकाई और खाद्य प्रसंस्करण आदि सहित कुल 55748 फसलोपरान्त प्रबंधन इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित की गई हैं तथा एमआईडीएच योजना के अंतर्गत स्थिर/मोबाइल वेंडिंग कार्ट/प्लेटफॉर्म, खुदरा दुकानें, ग्रामीण एवं प्राथमिक बाजार/अपनी मंडी/प्रत्यक्ष बाजार, थोक एवं टर्मिनल बाजार आदि सहित कुल 11140 मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित की गई हैं। चूंकि एमआईडीएच योजना राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, इसलिए रोजगार सृजन सहित लाभार्थी डेटा का रखरखाव राज्यों द्वारा किया जाता है।

*****